Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

जून 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 4
- इंदौर गौरव दिवस 5
- पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश सम्मानित 6
- खेल मंत्री ने किया शॉटगन के नये रेंज का उद्घाटन 8
- मध्य प्रदेश पर्यटन की 12 यूनिट्स ने जीता ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवलर्स च्वाइस का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 8
- एक ज़िला-एक उत्पाद योजना की मॉनीटरिंग के लिये समिति गठित 9
- 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ 9
- ईट राइट चैलेंज' प्रतियोगिता में भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान मिला 10
- राज्य स्तरीय मंजूरी समिति का पुनर्गठन 11
- प्रदेश में आरंभ होगा रिवर क्रूज टूरिज्म 11
- प्रदेश में आरंभ होगा रिवर क्रूज टूरिज्म 12
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन के लिये उत्तर प्रदेश के साथ होगा समझौता ज्ञापन 13
- लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर होगी क्रमश: 3000 रुपए 13
- 896 करोड़ से प्रदेश में बनेंगे 15 फ्लाई ओवर और रेलवे ओवर ब्रिज 14
- पन्ना ज़िले के हीरे को मिलेगा जीआई टैग 14
- एनएचडीसी इंदिरा सागर, खंडवा के पास 525 मेगावाट पंप भंडारण बिजली परियोजना का निर्माण करेगी 15
- शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना को प्राप्त हुआ B++ ग्रेड 15
- 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन 16
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन 17
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 18
- निवाड़ी बना प्रदेश का दूसरा हर घर जल ज़िला 20
- प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 34 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राज्य छात्रवृत्ति 20

नोट :

- उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार 21
- मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के संयुक्त क्राफ्ट बाज़ार का शुभारंभ 22
- मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का शुभारंभ किया 22
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी एवं मार्गदर्शन के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन 23
- क्रिस्प, मध्य प्रदेश और हरियाणा बीएसईएच ने किया समझौता 24
- लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25 हज़ार से बढ़कर 30 हज़ार रुपए प्रतिमाह होगी 25
- जल्द घोषित और लागू होगी मध्य प्रदेश की आई. टी. पॉलिसी 26
- प्रधानमंत्री ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पाँच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया 27
- मुरैना के कुलदीप दंडोतिया ने एशियन पेसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक 29
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 30

दृष्टि The Vision

नोट :

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

30 मई, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र. स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने के निर्णय के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद द्वारा म.प्र स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में संशोधन कर महिलाओं के समान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएँ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  - इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख रुपए की सहायता एवं चार चरण में अधिकतम 72 रुपए लाख की सीमा में देय होगी।
  - अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्ट-अप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत होनी चाहिये।
- मंत्रि-परिषद ने दमोह में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर निर्माण कार्यों के लिये 266 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की।
  - इस निर्णय से दमोह तथा समीपस्थ ज़िलों की जनता को तृतीयक स्तर की चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही प्रदेश के छात्रों के लिये चिकित्सा क्षेत्र की 100 एम.बी.बी.एस. सीटों की भी वृद्धि हो सकेगी।
- मंत्रि-परिषद ने वन्य-प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि एवं पशुहानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के वन विभाग के आदेश का कार्योत्तर अनुमोदन किया।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के ज़रूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लंबी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये संस्कृति विभाग में संचालित योजना 'कलाकार कल्याण कोष'को संशोधित करते हुए, नवीन 'मध्य प्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023' जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।
  - पहले की योजना में प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हज़ार रुपए तक की सहायता देने का ही प्रावधान था।
  - नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक है, जिसमें कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिये अधिकतम 50 हज़ार रुपए दिये जा सकेंगे।
  - शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार/साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिये अधिकतम एक लाख रुपए दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार/कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई-बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जाएगा।

नोट :

इंदौर गौरव दिवस

चर्चा में क्यों ?

31 मई, 2023 को भारत के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की वित्तीय राजधानी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में लोकमाता अहिल्या बाई के जन्म-दिवस के अवसर पर 'इंदौर गौरव दिवस' मनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले उमंग पार्क के कार्यों का तथा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा स्टार्टअप के सहयोग के लिये बनाए गए इन्क्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही सोलर सिटी के संकल्प-पत्र का विमोचन और वृक्ष एंबुलेंस का लोकार्पण भी किया।
- विदित है कि 298 साल पहले आज ही के दिन 1767 को देवी अहिल्या बाई का जन्म हुआ था। इसलिये उनके सम्मान में आज के दिन को पूरा शहर गौरव दिवस के रूप में मनाता है।
- देवी अहिल्या बाई होलकर मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास-प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थीं।
- 1754 में खंडेराव की युद्ध में वीरगति प्राप्त होने पर ससुर मल्हारराव होलकर ने अहिल्या देवी को होलकर साम्राज्य की कमान सौंप दी थी।
- 28 बरस के अपने शासनकाल में मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिये अहिल्या देवी का नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि पूरे भारत में करीब 65 मंदिर, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया।
- इसके अलावा सड़कें, कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ, घाट और पानी की टंकी को मूलभूत सुविधाओं के साथ बनवाया। महेश्वर में रहते हुए देश के दूरस्थ स्थलों, जैसे- अमरकंटक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, गंगोत्री, पुष्कर, मथुरा, रामेश्वर तथा हरिद्वार में धर्मशालाएँ बनवाईं।
- उल्लेखनीय है कि इंदौर भारत में एकमात्र शहर है, जहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम इंदौर) व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी इंदौर) दोनों स्थित हैं।

नोट :

पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानित किया। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास अवधेश शर्मा ने सम्मान प्राप्त किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक पर है।
- मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कुल 7 लाख 31 हज़ार 517 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से राज्य को आवंटित लक्ष्य 6 लाख 48 हज़ार 850 के विरुद्ध 7 लाख 8 हज़ार 894 प्रकरणों में ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना में प्रगति का प्रतिशत 109.25 है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (PM SVANidhi) या 'पीएम स्वनिधि' नामक योजना की शुरुआत की गई थी।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हिस्से के रूप में घोषित किया गया था।
- इसे 1 जून, 2020 से लागू किया गया था, ताकि उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने के लिये किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित योजना है, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :
  - कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना
  - नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना तथा
  - डिजिटल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना
- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैट्रल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिये एक वर्ष का समय दिया जाता है, विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकते हैं।
- साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिये गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण'(Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिये उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है। हालाँकि मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकते हैं।

नोट :

खेल मंत्री ने किया शॉटगन के नये रेंज का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में नव-निर्मित शॉटगन रेंज का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- 32 एकड़ में फैली शूटिंग अकादमी में लगभग 10 एकड़ में निर्मित इस नये शॉटगन रेंज में 5 रेंज बनाए गए हैं, जिसमें फाइनल रेंज, दो प्रशासकीय भवन और पवेलियन शामिल हैं।
- इस अवसर पर खेल मंत्री सिंधिया ने कहा कि नए शॉटगन रेंज में शॉटगन वर्ल्ड कप का आयोजन भी किया जा सकेगा। इसी कड़ी में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 11 से 18 जून तक शॉटगन के सिलेक्शन ट्रॉयल आयोजित कर रहा है।
- खेल मंत्री ने मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की समीक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र ही अकादमी के लिये टेलेंट सर्च करने और सी केटेगरी के बॉक्सर को वीड ऑउट करने के निर्देश भी दिये।

मध्य प्रदेश पर्यटन की 12 यूनिट्स ने जीता ट्रिप एडवाइजर्स ट्रेवलर्स च्वाइस का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि विश्व विख्यात पर्यटक मार्गदर्शी संस्था 'ट्रिप एडवाइजर'U.S. (यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका) के ट्रैवलर्स च्वाइस अवॉर्ड-2023 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की 12 इकाइयों ने ट्रिप एडवाइजर्स एनुअल ट्रैवलर्स च्वाइस अवार्ड जीता है।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि पलाश रेसीडेंसी भोपाल, बघीरा जंगल रिसॉर्ट मोचा, बायसन रिसॉर्ट मढ़ई, कलचुरी रेसीडेंसी जबलपुर, रॉक एंड मनोर पचमढ़ी, चंपक बंगलो पचमढ़ी, ग्लेन व्यू पचमढ़ी, होटल अमलतास पचमढ़ी, शीशमहल ओरछा, व्हाइट टाइगर फॉरेस्ट लॉज बांधवगढ़ एवं तानसेन रेसीडेंसी ग्वालियर को अवॉर्ड मिला है।
- वहीं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की ओरछा स्थित इकाई बेतवा रिट्रीट ने संस्था का 'बेस्ट ऑफ बेस्ट'अवार्ड 2023 जीता है।
- विदित है कि 'ट्रिप एडवाइजर'कंपनी संपूर्ण विश्व में विभिन्न स्थानों पर गए पर्यटकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन कर हर वर्ष यह अवार्ड प्रदान करती है।
- पर्यटकों की ओर से दुनियाभर के होटल, रेस्तरां और दूसरे स्थानों को दी हुई रेटिंग के आधार पर ट्रैवलर्स च्वाइस अवॉर्ड के लिये चुना जाता है। दुनिया भर के पर्यटक हर साल इसमें भाग लेते हैं और अपनी पसंद के आधार पर वोटिंग करते हैं।
- हर कैटेगरी में दुनिया के चुनिंदा 25 शहरों, पर्यटन स्थलों और होटल्स रेस्टोरेंट की सूची बनाकर प्रत्येक श्रेणी में अवार्ड की घोषणा की जाती है।
- उल्लेखनीय है कि निगम की समस्त इकाईयों में पर्यटकों के ठहरने के लिये पूर्णत: सुसज्जित अतिथि कक्षों, खान-पान, मनोरंजन गतिविधियाँ और आरामदायक स्टे की सुविधाएँ दी जाती है।
- पश्चिमी देशों विशेष कर फ्राँस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड आदि के पर्यटक विश्व के किसी भी देश में पर्यटन पर जाने के लिये उक्त संस्था द्वारा चिन्हित स्थानों, पूर्ण संरक्षित रात्रि विश्राम एवं खान-पान की दर, मात्रा एवं गुणवत्ता को विश्वास सहित प्राथमिकता देते हैं।

नोट :

एक ज़िला-एक उत्पाद योजना की मॉनीटरिंग के लिये समिति गठित

चर्चा में क्यों ?

1 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक ज़िला-एक उत्पाद एवं मूल्य संवर्धन योजना की मॉनीटरिंग के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- समिति के अन्य सदस्यों में अपर सचिव एवं प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन (मंडी बोर्ड), संचालक कृषि अभियांत्रिकी को शामिल किया गया है।
- समिति के सदस्य सचिव संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास होंगे।
- ज़िला स्तर पर एक ज़िला-एक उत्पाद योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में ज़िला स्तरीय समिति गठित होगी।
- समिति के सदस्य सचिव उप संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास होंगे।
- अन्य सदस्यों में परियोजना संचालक (आत्मा), महाप्रबंधक ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, सहायक कृषि यंत्री और ज़िला मुख्यालय स्तर पर सचिव मंडी समिति को शामिल किया गया है।

66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोज़गार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवक कल्याण विभाग और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मध्य प्रदेश के 2 शहर भोपाल एवं ग्वालियर में 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 13 जून तक किया जा रहा है।
- 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का ध्येय वाक्य 'जीत से बढ़कर खेल भावना' है।

नोट :

- प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के लगभग 5256 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- भोपाल एवं ग्वालियर के विभिन्न खेल मैदानों में एथलेटिक्स, फुटबाल, बालीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, टेबल टेनिस, हॉकी एवं बैडमिंटन की प्रतियोगिताएँ होंगी।

ईट राइट चैलेंज' प्रतियोगिता में भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान मिला

चर्चा में क्यों ?

7 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 'ईट राइट चैलेंज' प्रतियोगिता में खाद्य वातावरण में सुधार और खाद्य सुरक्षा पर समुदायों को शिक्षित करने की रणनीतियाँ लागू करने के प्रयासों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल को दूसरा और ग्वालियर को पाँचवां स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के सात अन्य ज़िले- उज्जैन, रीवा, इंदौर, सागर, दमोह, जबलपुर और सतना ने भी 75 प्रतिशत से अधिक अंक दर्ज कर विजेता सूची में स्थान प्राप्त किया।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. सत्यपाल सिंह बघेल ने इस अनुकरणीय प्रदर्शन के लिये विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- गौरतलब है कि ईट राइट चेलेंज के द्वितीय चरण में 1 मई, 2022 से 15 नवंबर, 2022 तक देश के 260 ज़िलों का खाद्य सुरक्षा के 6 विभिन्न मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 31 ज़िलों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किये थे।

नोट :

राज्य स्तरीय मंजूरी समिति का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी राजेश दाहिमा ने बताया कि राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिये गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को अधिक्रमित करते हुए समिति का पुनर्गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- पुनर्गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण, वित्त, योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जलसंसाधन, उद्यानिकी, सहकारिता, वन, कुलपति अथवा संचालक अनुसंधान सेवाएँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, आयुक्त/संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी, सहकारिता, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी, भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा नामित प्रतिनिधि, सदस्य होंगे।
- समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास समिति के सदस्य होंगे।
- समिति का कोरम भारत सरकार कृषि मंत्रालय से एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा। समिति की बैठक में कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं नेशनल रेनफेड एरिया एथोरिटी के वरिष्ठ अधिकारी/प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।
- समिति महत्त्वपूर्ण ज़िलों में से एक ज़िला कलेक्टर, सर्वोत्तम कृषक का पुरस्कार प्राप्त एक प्रगतिशील कृषक को पृथक् से नामित कर सकेगी।

प्रदेश में आरंभ होगा रिवर क्रूज टूरिज्म

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये रिवर क्रूज टूरिज्म का उपयोग किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात स्थित स्टेच्यु ऑफ यूनिटी तक आरंभ किया जाएगा। क्रूज 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
- बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि बरगी से मंडला तक भी क्रूज का संचालन आरंभ होगा।

नोट :

- रिवर क्रूज टूरिज्म के आरंभ होने से पर्यटक नर्मदा नदी के आस-पास उपलब्ध प्राकृतिक सौंदर्य और जैव-विविधता से रू-ब-रू हो सकेंगे।

प्रदेश में आरंभ होगा रिवर क्रूज टूरिज्म

चर्चा में क्यों ?

8 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये रिवर क्रूज टूरिज्म का उपयोग किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में रिवर क्रूज टूरिज्म का संचालन नर्मदा नदी में बड़वानी से गुजरात स्थित स्टेच्यु ऑफ यूनिटी तक आरंभ किया जाएगा। क्रूज 135 किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
- बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि बरगी से मंडला तक भी क्रूज का संचालन आरंभ होगा।
- रिवर क्रूज टूरिज्म के आरंभ होने से पर्यटक नर्मदा नदी के आस-पास उपलब्ध प्राकृतिक सौंदर्य और जैव-विविधता से रू-ब-रू हो सकेंगे।

नोट :

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन के लिये उत्तर प्रदेश के साथ होगा समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

11 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये 13 जून को लखनऊ में गांधी सभागार, राजभवन में समझौता ज्ञापन होगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह-2023 में 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत'के अंतर्गत दोनों राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन होगा।
- उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य और उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह एवं मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के विशिष्ट आतिथ्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे।
- मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिव शेखर शुक्ला और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम उपस्थित रहेंगे।

लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि बढ़कर होगी क्रमश: 3000 रुपए

चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'में बहनों के खातों में मासिक राशि अंतरित करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए योजना में लाड़ली बहनों को मिलने वाली मासिक 1000 की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में कुल 1209.64 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना'में प्रति माह 1000 रूपए की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा।
- आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में 1000 रुपए के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रुपए, फिर 1750 रूपए, फिर 2 हज़ार रुपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रुपए और 2750 रुपए करते हुए राशि को 3 हज़ार रुपए तक बढ़ाया जाएगा।
- इसी तरह योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की जाएगी। वर्तमान में 23 से 60 वर्ष की विवाहित बहनें योजना में पात्र हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों को आने वाले 5 वर्ष में लखपति बनाते हुए लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। बहनों की आय कम से कम 10 हज़ार रुपए मासिक होना चाहिये।

नोट :

896 करोड़ से प्रदेश में बनेंगे 15 फ्लाई ओवर और रेलवे ओवर ब्रिज

चर्चा में क्यों ?

10 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि प्रदेश में 'सेतु बंधन योजना' में 896 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाई ओवर तथा रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अविनाश लवानिया ने बताया कि इस योजना के तहत 4 फ्लाई ओवर इंदौर शहर में, दो फ्लाई ओवर भोपाल शहर में, दो फ्लाई ओवर सागर में तथा धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर और खंडवा में एक-एक फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
- दो रेलवे ओवर ब्रिज भी शीघ्र ही बनाए जाने हैं इसमें 36 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से भोपाल में छोला रोड काजी परेड़ से अयोध्या बायपास तथा 126 करोड़ रुपए से सिवनी शहर में एनएच-7 पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।

पन्ना ज़िले के हीरे को मिलेगा जीआई टैग

चर्चा में क्यों ?

9 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हीरा नगरी के रूप में विश्व-विख्यात पन्ना ज़िले के हीरे को जीआई टैग मिलेगा। इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ज़िला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र के मार्गदर्शन में ज़िले से प्राप्त होने वाले हीरों को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने के लिये गत दिनों चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री आवेदन किया गया था।

नोट :

- जीआई टैग मिलने की पुष्टि होने पर अब पन्ना के हीरों की चमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगी। पन्ना में हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
- विदित है कि एनएमडीसी द्वारा संचालित एक मात्र मेकेनाइज्ड खदान भी पन्ना में ही है। जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे की विशेष पहचान स्थापित होगी।

एनएचडीसी इंदिरा सागर, खंडवा के पास 525 मेगावाट पंप भंडारण बिजली परियोजना का निर्माण करेगी

चर्चा में क्यों ?

9 जून, 2023 को पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी लिमिटेड) मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य में पीक आवर की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना की शुरूआत की जा रही है। इसके लिये इंदिरा सागर परियोजना के मौजूदा जलाशयों इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर का इस्तेसमाल किया जाएगा।
- इस पंप भंडारण परियोजना के माध्यम से उत्पन्न अक्षय ऊर्जा में वृद्धि के साथ, राज्य की बिजली ज़रूरतों को पीक एनर्जी आवर्स (सुबह और शाम) के दौरान पूरा किया जा सकता है। परियोजना पीक आवर्स के दौरान 1,226.93 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पाहदन करेगी।
- इस परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने यह परियोजना एनएचडीसी लिमिटेड को आवंटित की है।
- मध्य प्रदेश में 11.2 गीगावॉट पंप भंडारण परियोजनाओं की क्षमता है। वर्तमान में खंडवा ज़िले में एनएचडीसी लिमिटेड के दो पावर स्टेशन- इंदिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मेगावाट) और ओंकारेश्वर पावर स्टेशन (520 मेगावाट) काम कर रहे हैं। इन पावर स्टेशनों द्वारा उत्पादित शत-प्रतिशत बिजली की आपूर्ति मध्य प्रदेश को की जाती है।
- एनएचडीसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के साथ हरित ऊर्जा के उत्पादन के जरिये राज्य को हरित राज्य बनाने की योजना बना रही है। ऐतिहासिक शहर सांची में 8 मेगावाट की सौर परियोजना और ओंकारेश्वर जलाशय पर 88 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना का निर्माण कार्य जारी है।
- गौरतलब है कि नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी लिमिटेड), मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड) का संयुक्त उद्यम है।

शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना को प्राप्त हुआ B++ ग्रेड

चर्चा में क्यों ?

12 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सागर ज़िले के बीना के शासकीय कन्या महाविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर की संस्था नैक द्वारा प्रत्यायन में बेहतर सीजीपीए ''2.76'' के साथ B++ ग्रेड प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार नैक के तृतीय चरण में महाविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बावजूद दो पायदान की बढ़ोतरी दर्ज की।
- तहसील स्थित इस महाविद्यालय ने पूर्व में प्राप्त ठ ग्रेड से दो पायदान छलांग लगाई है। महाविद्यालय का पूर्व में 2.27 सीजीपीए के साथ' B 'ग्रेड था।
- नैक द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में 7 मापदंड के आधार पर महाविद्यालय की गुणवत्ता का परीक्षण कर 4 में से अंक दिये जाते हैं। महाविद्यालय को स्टूडेंट सपोर्ट एवं प्रोग्रेशन (छात्र प्रगति) में 2.61, करिकुलर एस्पेक्ट में 2.8, संस्थागत मूल्यों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज में 3 अंक दिये गए।

नोट :

- महाविद्यालय की अधो-संरचना, मानवीय मूल्यों की शिक्षा एवं समाज विस्तार गतिविधियों की प्रशंसा की गई। गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट क्राइटेरिया में 2.6, अधो-संरचना एवं शिक्षण सुविधाओं में 2.8, रिसर्च, एक्सटेंशन एंड इनोवेशन में 2.09 एवं टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्यूएशन क्राइटेरिया में 2.98 अंक प्राप्त हुए हैं।
- वर्ल्ड बैंक द्वारा महाविद्यालयों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ महाविद्यालय द्वारा की गई कड़ी मेहनत एवं राज्य-स्तरीय नैक प्रकोष्ठ के सतत् प्रयत्नों से बेहतर "B ++" ग्रेड प्राप्त किया है।
- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में 'नई शिक्षा नीति 2020' के लागू करने से महाविद्यालयों द्वारा शिक्षण प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन कर छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित महिला महाविद्यालयों में भी लगातार प्रगति देखी जा रही है एवं महिलाओं की उच्च शिक्षा में सहभागिता निरंतर बढ़ रही है।

66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा खेल विभाग के सहयोग से भोपाल में हुई 66वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हो गया। आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव ने विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी एवं मेडल देकर पुरुस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- टेबल टेनिस (बालिका वर्ग) एकल मुकाबले में महाराष्ट्र की प्रथा वातिकार ने दिल्ली की प्रीतोकी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रीतोकी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दिल्ली की दिया ब्रह्मचारी एवं पश्चिम बंगाल की सुमित्रा दत्ता को काँस्य पदक मिला।
- टेबल टेनिस (बालक वर्ग) एकल मुकाबले में कर्नाटक के आकाश केजे ने अपने ही राज्य के रोहित को सीधे सेटों में 4-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रोहित को रजत पदक मिला। सीबीएसई के सार्थ मिश्रा एवं दिल्ली के अथर्व गुप्ता ने काँस्य पदक प्राप्त किया।
- टेबल टेनिस में बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की प्रथा वातिकार एवं बालक वर्ग में कर्नाटक के आकाश केजे को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया।
- टेबल टेनिस की बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप दिल्ली ने जीती, महाराष्ट्र दूसरे स्थान एवं हरियाणा तृतीय स्थान पर रहा। वहीं बालक वर्ग की टीम चैंपियनशिप कर्नाटक ने जीती, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान एवं सीबीएसई तृतीय स्थान पर रहा।
- जूडो में बालक वर्ग में आदित्य एवं बालिका वर्ग में अदिति शर्मा ने सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड जीता।

नोट :

- 70 प्लस वजन श्रेणी (बालिका वर्ग) में छत्तीसगढ़ की स्नेहा नियोगी ने महाराष्ट्र की संस्कृति को हराकर स्वर्ण पदक जीता। हिमाचल की निर्जल एवं राजस्थान की लावण्या ने काँस्य पदक प्राप्त किया।
- 90 किलो वजन श्रेणी (बालक वर्ग) में महाराष्ट्र के आदित्य ने हरियाणा के कुणाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुणाल को रजत से ही संतोष करना पड़ा, दिल्ली के रक्षक ने काँस्य पदक प्राप्त किया।
- जूडो की टीम चैंपियनशिप (बालक वर्ग) हरियाणा ने जीती, दिल्ली ने द्वितीय और पंजाब ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप दिल्ली ने जीती, महाराष्ट्र द्वितीय एवं हरियाणा तृतीय स्थान पर रहा।
- वॉलीबाल (बालक वर्ग) में गुजरात विजेता रहा। गुजरात ने एक रोमांचक मुकाबले में केरल को परास्त कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। द्वितीय स्थान पर केरल एवं तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल टीम रही।
- वॉलीबाल (बालिका वर्ग) में पश्चिम बंगाल की बालिकाओं ने महाराष्ट्र की बालिकाओं को हराकर बालिका वर्ग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, केरल तृतीय स्थान पर रहा।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

13 जून, 2023 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में लखनऊ में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और संस्कृति संवर्धन को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मध्य प्रदेश शिव शेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश मुकेश कुमार मेश्राम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत'अभियान की गतिविधियों के अंतर्गत दोनों राज्य एक-दूसरे की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देंगे।
- समझौता ज्ञापन के अनुसार उत्तर प्रदेश दिवस-24 जनवरी और गणतंत्र दिवस-26 जनवरी को उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के कलाकारों का समूह सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देगा। वहीं मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश के कलाकारों का समूह मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे।
- दोनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से आर्ट कम्पटीशन, एग्जिबिशन, सेमिनार, ड्रामा और थिएटर आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त आयोजन करने पर मेजबान राज्य स्थानीय आतिथ्य की व्यवस्था करेगा, वहीं आने वाला राज्य यात्राओं का खर्चा उठाएगा।
- दोनों ही प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराओं पर आधारित पुस्तक का निर्माण करेंगे और एक-दूसरे के प्रदेश के शैक्षिक संस्थानों में प्रदर्शित और वितरित करेंगे। दोनों ही प्रदेश अपने-अपने प्रदेश में एक-दूसरे के स्थानीय टीवी और रेडियो चैनल का प्रसारण करेंगे।
- समझौता ज्ञापन की अवधि 3 वर्ष की है, जिसे आपसी सहमति से 3 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।
- समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार एक दूसरे के संबंध को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। इस तरह के समझौतों से राज्य के नागरिक को भारत की विविधता को समझने, सराहना करने, समृद्ध बनाने और भारतीय संस्कृति रीति-रिवाजों और परंपराओं को जानने-समझने का अवसर प्राप्त होगा।
- इसके अलावा एक अन्य कार्यक्रम में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का प्रचार उत्तर प्रदेश में करने के लिये मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने लखनऊ के हजरतगंज में होटल गोमती में पर्यटन के मार्केटिंग कार्यालय का शुभारंभ किया गया।
- मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी समय में वाराणसी और अयोध्या में भी मार्केटिंग कार्यालय खोले जाने की योजना है।
- मार्केटिंग कार्यालय में कॉफी टेबल बुक, ब्रोशर, लीफलेट्स, मध्य प्रदेश मैप आदि से प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी और सेवाओं के बारे में उत्तर प्रदेश के निवासियों को बताया जाएगा। साथ ही पर्यटन निगम के होटल, रिसोर्ट, बोट क्लब के साथ उपलब्धियों, नवाचार और गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी। इससे उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

नोट :

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 'मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति, 2023' के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये नवीन योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
  - अगर एक से ज्यादा विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक हैं तो उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा।
  - जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है वहाँ पर स्कूटी प्रदाय की जाएगी।
  - योजना से लगभग 9 हज़ार विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
  - वर्ष 2023-24 के बजट में योजना के क्रियान्वयन के लिये 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुँचने की सुविधा बढ़ाने तथा निर्भरता कम करने, उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने, आत्म-विश्वास जागृत करने के लिये नवीन योजना का प्रावधान किया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा 15 अप्रैल, 2023 को जारी आदेश 'अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति' के लिये आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किये जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन छात्रवृति मानविकी विषयों के लिये भी दिये जाने का अनुसमर्थन किया।
  - साथ ही अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
  - उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है। आय सीमा में वृद्धि से अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के व्यापक अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- मंत्रि-परिषद ने 'मध्य प्रदेश की सहकारिता नीति, 2023' का अनुमोदन करते हुए समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर क्रियान्वित करने के लिये सहकारिता विभाग को अधिकृत किया है।

नोट :

- यह सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को एक जन-आंदोलन बनाने की दिशा में अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- सहकारिता के माध्यम से नवीन क्षेत्रों में समितियाँ गठित होंगी और रोज़गार के अवसर निर्मित होंगे।
- राज्य के सहकारिता कानून में भी आवश्यकतानुसार बदलाव किया जाएगा और सहकारिता की आंतरिक एवं संरचनात्मक कमियों को दूर करने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा।
- सहकारी नीति में कृषि साख, शहरी साख, सहकारी विपणन, सहकारी आवास, उपभोक्ता सहकारिता, सहकारी बीज उत्पादन एवं विपणन, लघु वनोपज सहकारी समितियाँ, डेयरी सहकारिता, सहकारी मत्स्य पालन आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

- मंत्रि-परिषद ने 600 मेगावॉट क्षमता की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना को राज्य शासन की भुगतान सुरक्षा गारंटी तथा उसके प्रारूप को सहमति प्रदान की है।
  - उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावॉट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरण में किया जा रहा है।
  - ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना देश तथा विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं में से एक होगी।
  - ओंकारेश्वर परियोजना देश की बहुउद्देश्यी परियोजनाओं में से एक है, जहाँ सिंचाई, जल विद्युत् उत्पादन के साथ अब सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
- मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप 'मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (CMYIPDP) में संशोधन की स्वीकृति दी है।
  - CMYIPDP प्रोग्राम में इंटर्न का मानदेय 8 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। इंटर्न की नियुक्ति अब ब्लॉक स्तर के साथ पंचायत स्तर पर की जाएगी।
- मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत सी.एम. राइज योजनांतर्गत 11 उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण कार्यों के लिये 338 करोड़ 83 लाख 6 हज़ार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
- उल्लेखनीय है कि जनजातीय कार्य विभाग में प्रथम चरण में 95 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। इसमें से धार, मंडला, झाबुआ, बैतूल, अलीराजपुर, खरगोन और रतलाम ज़िलों में कुल 11 स्कूल के लिये भवन निर्माण का कार्य किया जाना है।
- मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से क्रियान्वयन के लिये 2 पुनरीक्षित समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 2,002 करोड़ 62 लाख रुपए तथा 29 नवीन समूह जल प्रदाय योजनाएँ लागत 15,995 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया है।

नोट :

निवाड़ी बना प्रदेश का दूसरा हर घर जल ज़िला

चर्चा में क्यों ?

14 जून, 2023 को मध्य प्रदेश का निवाड़ी ज़िला प्रदेश का दूसरा हर-घर जल ज़िला बन गया है। ज़िले के सभी 253 ग्राम के शत-प्रतिशत 55 हजार 645 घर में नल से जल पहुँचाया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल ज़िला होने का गौरव प्राप्त है।
- प्रदेश में अब तक 50 प्रतिशत से अधिक (60 लाख 7 हजार से अधिक) घरों में नल से जल पहुँचाया जा चुका है। साथ ही जल की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
- निवाड़ी ज़िले में तीन समूह नल-जल योजनाओं से सभी ग्रामीण घरों में नल जल की व्यवस्था की गई है। निवाड़ी समूह नल-जल योजना से 30 ग्राम, निवाड़ी-पृथ्वीपुर-1 समूह नल-जल योजना से 143 ग्राम और निवाड़ी-पृथ्वीपुर-2 समूह नल-जल योजना से 80 ग्राम के शत-प्रतिशत घरों में नल से जल सुविधा प्रदाय की गई है।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के 34 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी राज्य छात्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

15 जून, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के 34 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि प्रदेश में कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक सुधार के लिये पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा राज्य छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इस वर्ष इस योजना का लाभ 34 लाख विद्यार्थियों को दिलाया जाएगा।
- विभाग ने योजना के लिये इस वर्ष बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विभाग ने पिछले वर्ष 2022-23 में इस योजना में 222 करोड़ रुपए की राशि, राज्य छात्रवृत्ति के रूप में खर्च की थी।
- योजना में इन वर्गों के उन विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति का फायदा दिया जाता है, जिनके अभिभावक की आय, आयकर की सीमा में नहीं आती है।

नोट :

- गौरतलब है कि पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये तीन महान व्यक्तियों के नाम पर पुरस्कार योजना संचालित की जा रही है।
- योजना में चयनित समाज सेवियों को शहीद अशफाकउल्ला खां, कैप्टन हमीद खां और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- योजना के क्रियान्वयन के लिये विभाग ने वर्ष 2023-24 में 47 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया है।
- पुरस्कारस्वरूप चयनित व्यक्ति को एक लाख रुपए की राशि सम्मानस्वरूप प्रतीक-चिन्ह के साथ भेंट की जाती है।
- राज्य शासन ने यह पुरस्कार योजना वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की है।

उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

17 जून, 2023 को उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को जल-संरक्षण, प्रबंधन एवं उपयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिये सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और अपर मुख्य सचिव एस.एन. मिश्र को प्रथम पुरस्कार के प्रशस्ति-पत्र और ट्रॉफी से सम्मानित किया।
- यह देश का चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2022 है। कार्यक्रम में 11 विभिन्न श्रेणी में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंदौर नगर निगम को जल आपूर्ति तथा वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन को प्रशस्ति-पत्र, ट्रॉफी और एक लाख 50 हज़ार रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया।
- मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि विगत 18 वर्ष में प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसे वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर किये जाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश में बांध से सीधे खेतों तक भूमिगत पाइप लाइन से जल पहुँचाने का नवाचार हुआ है। प्रदेश की मोहनपुरा एवं कुंडालिया परियोजना, जिसकी सिंचाई क्षमता 2 लाख 25 हज़ार हेक्टेयर है, जल उपयोग दक्षता उन्नयन के क्षेत्र में अनुकरणीय सिंचाई परियोजना के रूप में स्थापित हो चुकी है।

नोट :

मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के संयुक्त क्राफ्ट बाज़ार का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव और आंध्र प्रदेश की प्रमुख सचिव के. सुनीता ने भोपाल के गोहर महल में दोनों राज्यों के संयुक्त 'क्राफ्ट बाज़ार'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन और वस्त्र मंत्रालय आंध्र प्रदेश द्वारा भोपाल में गोहर महल में 16 से 25 जून तक 'क्राफ्ट बाजार'का आयोजन किया जा रहा है।
- आयुक्त सह प्रबंध संचालक संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम सूफीया वली फारूकी ने बताया कि 25 जून तक हो रहे 'क्राफ्ट बाज़ार'में मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश के शिल्पियों द्वारा उत्पादित सामग्री विक्रय के लिये उपलब्ध है।
- आयुक्त हस्तशिल्प फारूकी ने बताया कि मध्य प्रदेश और आंध्रप्रदेश के बीच सहमति के आधार पर प्रदेशवासियों को आंध्र प्रदेश का शिल्प उपलब्ध कराने के लिये आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी एम्पोरियम की वस्तुओं को मृगनयनी शो-रूम में प्रदर्शित किया जाएगा। यह विक्रय के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

19 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होटल आमेर ग्रीन भोपाल में एकदिवसीय राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यस्तरीय एमएसएमई समिट का ध्येय वाक्य 'आर्थिक विकास के शुभ संयोग-मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग'रखा गया था।
- समिट का आयोजन प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों और उनसे सृजित रोज़गार के प्रोत्साहन के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया गया।

नोट :

- कार्यक्रम में प्रदेश के 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें उद्यमी एवं उद्योगपति, उद्योग संघ पदाधिकारी, स्टार्टअप से जुड़े व्यक्ति और विद्यार्थी शामिल थे। प्रदेश के सभी ज़िले कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े।
- समिट का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देना, नवाचार की भावना को विकसित करना तथा राज्य के विकास में एमएसएमई के योगदान को उजागर करने के साथ ही एक समग्र एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करना है।
- समिट में मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिये राज्यस्तरीय एमएसएमई पुरस्कार प्रदान किये।
- प्रभावी कार्य संस्कृति और बेस्ट प्रेक्टिसेस अपनाने के लिये वर्ष 2018-19 का प्रथम पुरस्कार आईटीएल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंदौर को, द्वितीय पुरस्कार शास्त्री सर्जिकल इंडस्ट्रीज रायसेन और तृतीय पुरस्कार शक्ति एम्पोरियम झाबुआ को प्रदान किया गया। महिला उद्यमियों में मंत्रा कम्पोजिट इंदौर की ममता महाजन को पुरस्कृत किया गया।
- वर्ष 2019-20 के लिये नंदिनी मेडिकल लेबोरेट्रीज इंदौर को प्रथम, न्यू लाईफ लेबोरेट्रीज मंडीदीप रायसेन को द्वितीय और सेफफ्लेक्स इंटरनेशनल धार को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
- वर्ष 2020-21 के लिये मॉर्डन लेबोरेट्रीज इंदौर को प्रथम, डीइसीजी इंटरनेशनल मंडीदीप रायसेन को द्वितीय और हेल्थीको क्वालिटी प्रोडक्ट्स धार को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- वर्ष 2020-21 में महिला उद्यमियों की श्रेणी में सांई मशीन टूल्स इंदौर की शिखा विशाल जायसवाल और निहारिका अजय जायसवाल तथा अर्थव पैकेजिंग इंदौर की ममता शर्मा को पुरस्कृत किया गया।
- इस समिट में राज्य सरकार एवं देश की प्रतिष्ठित कंपनी और संस्थानों के बीच एम.ओ.यू का आदान-प्रदान भी हुआ।
- एनएसई इंडिया, वॉलमार्ट, आरएक्सआईएल, इनवॉइस मार्ट तथा आइसेक्ट के साथ एम.ओ.यू. हुए।
- इन एमओयू के निष्पादन से प्रदेश की एमएसएमई को पूंजी जुटाने के अवसर प्राप्त होंगे, ट्रेड प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई को ऑनबोर्ड करने में सुविधा होगी और एमएसएमई के समग्र विकास में ये सभी संस्थाएँ राज्य शासन के साथ मिल कर कार्य करेंगी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी एवं मार्गदर्शन के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

21 जून, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने मिशन शक्ति योजना-संबल एवं सामर्थ्य उपयोजना के अंतर्गत संबंधित विभागों से समन्वय तथा ज़िला एवं राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन की निगरानी व मार्गदर्शन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस राज्य स्तरीय समिति में प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव होंगे।
- सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल एवं रोजगार, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी, गृह, खेल एवं युवा कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विधि और विधायी कार्य समिति में सदस्य होंगे।
- समिति द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत योजनाओं की राज्य स्तरीय वार्षिक कार्य-योजना तैयार करने एवं वर्ष में कम से कम 2 बार निगरानी बैठक आयोजित किये जाने का कार्य किया जाएगा। समिति का कार्यकाल 15वें वित्त आयोग की अवधि तक होगा।

क्रिस्प, मध्य प्रदेश और हरियाणा बीएसईएच ने किया समझौता

चर्चा में क्यों ?

25 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार क्रिस्प, मध्य प्रदेश द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक से हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच) को डिजिटल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और ऑनलाइन सत्यापन सेवा प्रदान करेगा। इसके लिये क्रिस्प मध्य प्रदेश और बीएसईएच के बीच 22 जून को एग्रीमेंट हुआ।

प्रमुख बिंदु

- यह एग्रीमेंट दोनों संस्थाओं के बीच 3 साल के लिये हुआ है, जिसमें प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक नियमित और पूरक परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। सार्वजनिक ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर ब्लॉकचेन डिजिटल प्रमाण-पत्र तैयार करने के बाद प्रमाण-पत्र की प्रोसेसिंग की जाएगी।
- बीएसईएच की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिये छात्रों को एंक्रिप्टेड डिजिटल प्रमाण-पत्र भी दिये जाएंगे, जिसमें बोर्ड के पास एंक्रिप्टेड रिकॉर्ड्स का उपयोग करके रिकॉर्ड की भौतिक प्रतियों की छपाई का भी प्रावधान होगा।
- क्रिस्प के प्रबंध निदेशक डॉ. श्रीकांत पाटिल ने बताया कि हरियाणा सरकार के साथ अपनी तरह की यह अनोखी पहल है, जिसमें छात्रों की बेहतरी के लिये क्रिस्प द्वारा विकसित ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में भारत के विभिन्न राज्यों के साथ भी काम करेंगे।
- संस्था को केपेबिलिटी मैच्युरिटी इंटीग्रेशन स्तर 5 का प्रमाणन भी प्राप्त है, जिसे आई.टी और ई-गवर्नेंस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रमाणन माना जाता है।
- क्रिस्प के निदेशक अमोल वैद्य ने बताया कि ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणन प्रणाली का उद्देश्य पहचान की चोरी से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों से बचाव करना और छात्रों को सही प्रमाण-पत्र देना है।
- क्रिस्प के आई टी प्रमुख संदीप जैन ने बताया कि क्रिस्प मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी विभिन्न विभागों को अत्याधुनिक आईटी-सक्षम सेवाएँ प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य क्रिस्प को कौशल विकास का पर्याय बनाना है।
- विदित है कि क्रिस्प, शिक्षा प्रणाली में ऐसी उन्नत तकनीक लाने के लिये भारत भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ काम कर रहा है।
- ब्लॉकचेन-आधारित प्रमाणन प्रणाली किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अपनी तरह का पहला कार्यान्वयन है, जो बीएसई हरियाणा द्वारा उम्मीदवार को एक विकेंद्रीकृत मैकेनिज़्म के माध्यम से इंडिविजुअल/विशिष्ट डेटा को सत्यापित करते हुए रिकॉर्ड की प्रामाणिकता प्रदान करेगा।
- सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (क्रिस्प) प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्र में पिछले 27 वर्षों से काम करता आ रहा है। यह संस्थान आईटी क्षेत्र में समाधान भी प्रदान करता है।
- क्रिस्प, भविष्यवादी प्रौद्योगिकी लैब, ब्लॉकचेन/एआई/एमएल/रोबोटिक ऑटोमेशन और अन्य भविष्य की प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उन्नत आईटी समाधान विकसित करता आ रहा है।

नोट :

लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 25 हज़ार से बढ़कर 30 हज़ार रुपए प्रतिमाह होगी

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में उनके निवास परिसर में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में लोकतंत्र सेनानियों को प्रदान की जा रही 25 हज़ार रुपए की सम्मान निधि को बढ़ाकर 30 हज़ार रुपए प्रतिमाह किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो लोकतंत्र सेनानी एक माह से कम अवधि के लिये बंदी रहे हैं, उनकी सम्मान निधि 8 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए की जाएगी।
- दिवंगतों के परिवारों को दी जाने वाली निधि भी 5 हज़ार से बढ़ाकर 8 हज़ार रुपए की जाएगी।
- लोकतंत्र सेनानियों को दिल्ली प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश भवन में ठहरने की सुविधा होगी। जिलों के विश्राम गृह और रेस्ट हाऊस में वे 2 दिन तक 50 प्रतिशत शुल्क देकर रह सकेंगे। साथ ही सभी तरह की बीमारियों का संपूर्ण इलाज राज्य शासन द्वारा कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कार्यालयों में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, इसके लिये विशेष निर्देश जारी किये जा रहे हैं।
- लोकतंत्र सेनानियों को राज्य शासन की ओर से ताम्रपत्र प्रदान किये गए थे, जिन्हें ताम्रपत्र मिलना शेष है, उन्हें भी तत्काल ताम्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

नोट :

- सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने आपातकाल की कटु स्मृतियों पर आधारित रमेश गुप्ता की पुस्तक 'मैं मीसाबंदी-आपातकाल व्यथा-कथा-19 महीने'का विमोचन भी किया।

जल्द घोषित और लागू होगी मध्य प्रदेश की आई. टी. पॉलिसी

चर्चा में क्यों ?

26 जून, 2023 को मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि मध्य प्रदेश की आईटी-आईटीईएस और ईएसडीएम नीति शीघ्र ही घोषित और लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- एमएसएमई मंत्री ने बताया कि इस नीति का लक्ष्य सभी कारकों का समावेश कर आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है।
- राज्य में अनुसंधान एवं विकास, निवेश, रोज़गार, नवाचार और उद्योगों के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर इस नीति में विशेष ध्यान दिया गया है।
- उन्होंने बताया कि 2023 के लिये मध्य प्रदेश की आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम नीति उद्योग जगत से विचार-विमर्श के विभिन्न सत्रों और विभिन्न राज्य की नीतियों की बेंचमार्किंग के पश्चात् बनाई गई है।
- नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। यह नीति व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- मंत्री सखलेचा ने बताया कि नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्र में 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर 2 लाख नई नौकरियाँ सृजित करना है।
- इसमें 10 मिलियन वर्गफुट आईटी, ईएसडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस का निर्माण, राज्य भर में अत्याधुनिक आईटी पार्क, भवन, प्लग एंड प्ले स्पेस को आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम के लिये प्लग एंड प्ले और रेडी टू बिल्ड फैक्टरियाँ शामिल कर बुनियादी ढाँचा खड़ा करने पर ज़ोर दिया गया है।

नोट :

- एमएसएमई मंत्री ने बताया कि ड्राफ्ट नीति नवीन विशेषताएँ प्रस्तुत करती है, जो उद्योग के समक्ष आने वाली महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान भी सुझाएगी। ड्राफ्ट नीति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिये CAPEX सहायता का विशेष प्रावधान प्रदान करके विश्व स्तरीय आईटी बुनियादी ढाँचा विकसित करने के प्रावधान शामिल हैं।
- नीति में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूंजी सब्सिडी कैपिंग को बढ़ाकर उनका समर्थन किया गया है।
- प्रारूप नीति में ईएसडीएम इकाइयों में निवेश आकर्षित करना, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना और एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना शामिल है।
- नीति व्यवसायों को अपना संचालन स्थापित करने में मदद करने के लिये किराये में सहायता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने के लिये रोज़गार सृजन सहायता प्रदान करती है।
- यह नीति टेस्टिंग, कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंटिंग और स्टैंड अलोन शोध और विकास इकाइयों का समर्थन करने के लिये विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यम से प्रतिष्ठानों को सहायता प्रदान करके अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है।
- ड्राफ्ट नीति राज्य में विभिन्न प्रकार के डेटा सेंटर्स को आकर्षित करने पर ज़ोर देती है। नीति में डेटा सेंटर इकाइयों के लिये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रावधान विशेष रूप से तैयार किये गए हैं। नीति में अनुकूलित पैकेज के माध्यम से क्षेत्र में मेगा परियोजनाओं का समर्थन करने का भी प्रावधान है।
- नीति का लक्ष्य आईटी-ईएसडीएम क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिये एक जीवंत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जिससे मध्य प्रदेश को आईटी के लिये एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पाँच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के पाँच नए एवं उन्नत संस्करणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राजधानियों को जोड़ती हैं।

प्रमुख बिंदु

- आरामदायक और उन्नत अनुभव वाली रेल यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करते हुए, रानी कमलापति-जबलपुर, रानी कमलापति-इंदौर, गोवा (मडगाँव)-मुंबई, राँची-पटना और धारवाड़-बेंगलुरु के बीच पाँच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गईं हैं।
- इन पाँच नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मिलाकर अब देश में कुल 23 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। ये ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों की तुलना में यात्रा के समय में कई घंटों की बचत कर रही हैं।
- आज रवाना की गईं ये वंदे भारत ट्रेनें विभिन्न राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, यात्रा में लगने वाले समय को कम करेंगी तथा यात्रा को और आरामदायक बनाएंगी।
- रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस:
  - रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और नरसिंहपुर, पिपरिया तथा नर्मदापुरम रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन जबलपुर स्टेशन पहुँचेगी।
  - रानी कमलापति-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस महाकौशल क्षेत्र (जबलपुर) को मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र (भोपाल) से जोड़ेगी।
  - वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू होने से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और आसपास के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ-साथ इस इलाके का सर्वांगीण विकास भी होगा।
  - इस ट्रेन के चलने से भोपाल से जबलपुर की 340 किमी. की दूरी अब साढ़े चार घंटे में ही तय हो जाएगी।

नोट :

- रानी कमलापति-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस:
  - भोपाल-इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करेगी और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए उसी दिन इंदौर स्टेशन पहुँचेगी।
  - रानी कमलापति से इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन के चलने से भोपाल से इंदौर की 269 किमी. की दूरी अब साढ़े तीन घंटे में तय हो जाएगी। साथ ही, यह इन इलाकों की संस्कृति, पर्यटन और तीर्थ स्थलों को जोड़ने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेगी।
- गोवा (मडगाँव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस:
  - गोवा (मडगाँव)-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से प्रस्थान करेगी और दादर, ठाणे, पनवेल, खेड़, रत्नागिरी, कंकावली तथा थिविम रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन मडगाँव स्टेशन पहुँचेगी।
  - यह अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस कोंकण क्षेत्र के लोगों को गति और आराम के साथ यात्रा करने का साधन उपलब्ध कराएगी। इससे इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है कि इस मार्ग पर चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन पर्यटकों की सुविधा में नए आयाम जोड़ेगी।
- राँची-पटना वंदे भारत एक्सप्रेस:
  - राँची-पटना नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से प्रस्थान करेगी और गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना तथा मेसरा रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन राँची स्टेशन पहुँचेगी।
  - प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों से समृद्ध, राँची खनिज आधारित उद्योगों के लिये एक आदर्श स्थान है। यह ट्रेन स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों के लिये पटना के साथ तेज कनेक्टिविटी स्थापित करने की दृष्टि से लाभदायक साबित होगी।
- धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस:
  - धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केएसआर बेंगलुरु सिटी से प्रस्थान करेगी और यशवंतपुर, दावणगेरे तथा हुबली रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन धारवाड़ स्टेशन पहुँचेगी।
  - कर्नाटक में, धारवाड़-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन विद्या काशी धारवाड़, वाणिज्य नगरी, हुबली और बेंगलुरु को जोड़ेगी। यह वंदे भारत ट्रेन उत्तरी कर्नाटक को दक्षिणी कर्नाटक से जोड़ेगी।
- वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें कई प्रकार की बेहतर सुविधाएँ प्रदान करती हैं, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय आरामदायक यात्रा का अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा संबंधी विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।
- प्रत्येक ट्रेन में 160 किमी. प्रति घंटे की परिचालन गति के लिये पूरी तरह से सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर से लैस बोगियाँ प्रदान की गई हैं। उन्नत अत्याधुनिक सस्पेंशन प्रणाली यात्रियों के लिये सुगम एवं सुरक्षित यात्रा और बेहतर आरामदायक सवारी सुनिश्चित करती है।
- इन ट्रेनों को पावर कार और उन्नत पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लगभग 30 प्रतिशत बिजली की बचत करके भारतीय रेल के हरित उत्सर्जन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।

नोट :

मुरैना के कुलदीप दंडोतिया ने एशियन पेसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

27 जून, 2023 को हांगकांग में चल रही एशियन पेसिफिक पावर लिफ्टिंग एंड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले के पावर लिफ्टर कुलदीप दंडोतिया ने स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- हांगकांग में चल रही इस प्रतियोगिता में कुलदीप दंडोतिया ने जूनियर वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है।
- हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम में कुलदीप दंडौतिया ने 120 किग्रा. प्लस जूनियर कैटेगिरी के तीन राउंड में क्रमश: 95 किग्रा., 105 किग्रा. और 115 किग्रा. वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी 107.5 किग्रा. व न्यूजीलैंड के खिलाड़ी 102.5 किग्रा. वेट उठाकर क्रमश: दूसरे व तीसरे नंबर पर रहे।
- मुरैना ज़िले के देवरी गाँव के रहने वाले पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी कुलदीप दंडोतिया ने अभी हाल ही में 17 से 27 मई तक साउथ अफ्रीका के सन सिटी शहर में विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था।

नोट :

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

28 जून, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में विद्युत वितरण कंपनियों के लिये 24 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण मदों में स्वीकृति दी गई।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश में 33 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के लिये अनुमानित लागत 1335 करोड़ 20 लाख रुपए में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सी.एम. राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं।
- मंत्रिपरिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये 'अटल गृह ज्योति योजना'में स्वीकृत सब्सिडी एवं विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में 24 हज़ार 196 करोड़ 47 लाख रुपए की सब्सिडी स्वीकृति दी गई।
- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधो-संरचना विकास के लिये 'मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना'चतुर्थ चरण को दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25) के लिये 1700 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रि-परिषद द्वारा खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ तथा सीधी ज़िलों में 100 एम.बी.बी.एस सीटों की प्रवेश क्षमता वाले नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जाने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है।
- 'दीनदयाल रसोई योजना' में पूर्व में स्थापित 100 रसोई केंद्रों के अतिरिक्त, 20 नवीन स्थायी रसोई केंद्र तथा ऐसे लोगों की मदद के लिये जो स्थायी रसोई केंद्रों पर नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिये 16 नगर निगमों तथा पीथमपुर एवं मंडीदीप में कुल 25 नवीन चलित रसोई केंद्र, इस प्रकार कुल 45 नवीन रसोई केंद्र खोले जाने एवं मात्र रुपए 5 प्रति व्यक्ति की दर से रसोई में भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा केंद्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की 'प्राइस सपोर्ट स्कीम'में प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के उपार्जन पर मंडी शुल्क की छूट के साथ निराश्रित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राइस सपोर्ट स्कीम में वर्ष 2022 (विपणन मौसम 2022-23) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूँग एवं ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा सीप-अंबर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 लागत राशि 190 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना से सीहोर ज़िले की भैरूंदा तहसील के 24 ग्रामों की 13 हज़ार 457 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 19 अगस्त, 2013 से संचालित 'मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना'को 31 मार्च, 2019 के पश्चात् से निरंतर बनाए रखते हुए आगामी पाँच वर्ष तक निरंतर संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रि-परिषद द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड छ. क्रमांक 4 के परिशिष्ट-1 (एक) (ख) की तालिका में केले की फसल हानि पर वर्तमान में आर्थिक अनुदान सहायता के लिये निर्धारित मापदंडों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- केले की फसल में 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर 30 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि, 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 54 हज़ार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि एवं 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान सहायता राशि करने की स्वीकृति दी गई।
- आर्थिक अनुदान सहायता राशि की अधिकतम देय सीमा 3 लाख रुपए के स्थान पर 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

नोट :